(गोरख पाण्डेय की कविताएं)

अमीरों का कोरस

जो है ग़रीब उनकी जरूरतें कम हैं
कम हैं जरूरतें तो मुसीबतें कम हैं
हम मिल–जुल के गाते ग़रीबों की महिमा
हम महज अमीरों के तो गम ही गम हैं

वे नंगे रहते हैं बड़े मज़े में
वे भूखों रह लेते हैं बड़े मज़े में
हमको कपड़ों पर और चाहिए कपड़े
खाते–खाते अपनी नाकों में दम है

वे कभी–कभी कानून भंग करते हैं
पर भले लोग़ हैं, ईश्वर से डरते हैं
जिसमें श्रद्धा या निष्ठा नहीं बची है
वह पशुओं से भी नीचा और अधम है

अपनी श्रद्धा भी धर्म चलाने में है
अपनी निष्ठा तो लाभ कमाने में है
ईश्वर है तो शांति, व्यवस्था भी है
ईश्वर से कम कुछ भी विध्वंस परम है

करते हैं त्याग गरीब स्वर्ग जाएंगे
मिट्टी के तन से मुक्ति वहीं पायेंगे
हम जो अमीर हैं सुविधा के बंदी हैं
लालच से अपने बंधे हरेक कदम हैं

इतने दुख में हम जीते जैसे–तैसे
हम नहीं चाहते ग़रीब हों हम जैसे
लालच न करें, हिंसा पर कभी न उतरें
हिंसा करनी हो तो दंगे क्या कम हैं

जो ग़रीब हैं उनकी जरूरतें कम हैं
कम हैं मुसीबतें, अमन चैन हरदम है
हम मिल–जुल के गाते ग़रीबों की महिमा
हम महज अमीरों के तो गम ही गम हैं

उसको फांसी दे दो

वह कहता है उसको रोटी–कपड़ा चाहिए
बस इतना ही नहीं, उसे न्याय भी चाहिए
इस पर से उसको सचमुच आज़ादी चाहिए
उसको फ़ांसी दे दो।

वह कहता है उसे हमेशा काम चाहिए
सिर्फ़ काम ही नहीं, काम का फल भी चाहिए
काम और फल पर बेरोक दख़ल भी चाहिए
उसको फ़ांसी दे दो।

वह कहता है कोरा भाषण नहीं चाहिए
झूठे वादे हिंसक शासन नहीं चाहिए
भूखे–नंगे लोग़ों की जलती छाती पर
नक़ली जनतंत्री सिंहासन नहीं चाहिए
उसको फ़ांसी दे दो।

वह कहता है अब वह सबके साथ चलेगा
वह शोषण पर टिकी व्यवस्था को बदलेगा
किसी विदेशी ताक़त से वह मिला हुआ है
उसको इस गद्दारी का फल तुरत मिलेगा
आओ देशभक्त जल्लादो!
पूंजी के विश्वस्त पियादो!
उसको फांसी दे दो।

(किसान क्रांतिकारियों को फ़ांसी
दिए जाने पर 1978 में)

पेज 1 का शेष

बी.जे.पी. का इलैक्शन मेनिफेस्टो उर्फ मोदीफेस्टो

सबसे महत्त्वपूर्ण बात ये है कि आर्थिक नीतियों–उदारीकरण, निजीकरण, विदेशी पूंजी निवेश आदि, जैसे महत्त्वपूर्ण और जीवन–मरण के प्रश्नों पर कुछ खास नहीं कहा गया है। जिसका सीधा सा निष्कर्ष यही निकलता है कि मोदी कांग्रेस की ही आर्थिक नीतियों को जारी रखेंगे। इसलिये आम जनता को अगाह हो जाना चाहिये कि मोदी चाहे कितनी ही बगले बजायें लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की मार कम नहीं होने जा रही है बल्कि मोदी का कोड़ा आम जनता की पीठ पर और जोर से पड़ने जा रहा है ताकि वो अंबानियों और अदानियों के लिये और ज़्यादा कमा कर दे सके।

देश नहीं मिटने दूंगा से शायद मोदी का तात्पर्य भी यही है कि वे अंबानियों और अदानियों के साम्राज्य में कोई कमी नहीं आने देंगे, गरीब जनता चाहे रसातल में ही क्यों न जाये।

दिखावे के तौर पर मोदी ने चाहे कितना ही विकास का ढोल पीटा हो लेकिन उनके चुनाव अभियान का मुख्य बिन्दु मुसलमानों के प्रति जहर भर के हिन्दू वोटों को इकट्ठा करना ही था। इसी के तहत अमितशाह को यूपी में प्रभारी बनाकर भेजा गया और जाकर उन्होंने मुज़फ़्फ़रनगर में दंगे करवाये। इसी के तहत मेनिफेस्टो में राम मन्दिर बनाने और धारा 370 हटाने का जिक्र है। सच तो यह है कि जब मोदी देश नहीं मिटने और बिकने दूगा की बात कर रहा है तो वह वास्तव में देश यानी हिदुओं को मुसलमानों से बचाने की बात कर रहा है और अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों को हिन्दुओं का और इस देश का दुश्मन घोषित कर रहा है। दुर्भाग्य से अब तक वह अपने इस मकसद में कामयाब होता प्रतित होता है। देश की भोली–भाली धर्म भीरू जनता मोदी और उसके थैलीशाहों की कुटिल चालों में फंस गई लगती है। भक्षक को ही रक्षक समझने लगी है।

अपने इसी षडयंत्र के तहत मोदी अब तक सिर्फ इकतरफ़ा भाषण झाड़ने में लगा हुआ है। यह देश के इतिहास में पहला मौका है जब कोई पार्टी एक पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर चुनाव लड़ रही है। और वह व्यक्ति किसी तरह की बहस को तैयार नहीं, किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं, कोई अपना भावी कार्यक्रम, कोई आर्थिक नीति बताने को तैयार नहीं। पार्टी अध्यक्ष का हाल यह है कि वह ट्वीट्ट पर नारा देते हैं कि 'अबकी बार भाजपा सरकार' और 32 मिनट में ही उसे वापस लेकर 'अबकी बार मोंदी सरकार' मिमियाने लगते हैं। यह वही पार्टी है जो मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री बताते नहीं थकती लेकिन अपने अध्यक्ष का गला दबाये हुये हैं। ना आडवाणी नजर आ रहे हैं ना सुषमा सवराज । ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है ना दीन दयाल उपाध्याय को। बस मोदी–मोदी। कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई जवाब नहीं मांग सकता। यह वही मोदी है जो दो बार टी.वी.–पर बहस से भाग चुका है, जो किसी के सवालों के जवाब नहीं देता सिर्फ भाषण देता है, अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनता है और चलता बनता है।

अब इस मोदीफेस्टो के जारी होने से लोगों को यह जानने की रही सही आस भी जाती रही है कि आखिर बी.जे.पी. के पास या मोदी के पास इस देश की समस्याओं का समाधान क्या है। बढती महंगाई और बेरोज़गारी कैसे रूकेगी। अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मिलेंगे? क्या सिर्फ मुसलमानों को मारकर इस देश के सभी लोग़ों को ये चीजें हासिल हो जायेंगी? यदि नहीं तो इस देश के लोग़ों को मोदी या बी.जे.पी. से ये जानने का हक है। अगर वह ये बातें अपने मोदीफेस्टों में नहीं बता रहे तो देश की जनता को मोदी की सभाओं में खड़े होकर ये सवाल पूछने का हक है।

संसदीय लोकतंत्र को खतरा

–डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इस शासन प्रणाली में संसद बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। संविधान के अनुसार संसद के दो सदन हैं–एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसके सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्य सभा उच्च सदन है जो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करता है। संसद के प्रमुख कार्य हैं–कानून बनाना, बजट पारित करना, सरकार (मंत्रिमंडल) को सजग रखना, सरकार की नीतियों की, कमियों की, आलोचना करना, जनता की समस्याओं से संबंधित मुद्दे सदन में उठाना और उन पर सार्थक बहस करना आदि।

संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद/विधायक को अपनी राय प्रकट करने व अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का अधिकार है, जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया व नियम हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से सभी नियमों, प्रक्रियाओं व मापदंडों का बेखौफ और बेफिक्री के साथ उल्लंघन हो रहा है। जन समस्याओं पर सार्थक बहस करने व वैचारिक कार्य करने की अपेक्षा सांसद व विधायक सदन में हो हल्ला व शर्मनाक नाटक करके सदन की कार्यवाही को ठप कर देते हैं और कई बार तो पूरा का पूरा सत्र बिना कोई कार्यवाही किए शोर–शराबे का शिकार हो जाता है। आश्चर्य है कि बिना कोई कार्य किए इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने वेतन व भत्ते लेते कोई शर्म भी नहीं आती।

संसद की कार्यवाही को जानबूझकर ठप्प कर समय बर्बाद करने के मामले में 15 वीं लोक सभा ने एक नया रिकार्ड बना दिया है। लगातार आसमान छूती मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढती आर्थिक असमानता, सरकार के आर्थिक घोटाले तथा नव उदारवाद नीतियों पर चलने के फलस्वरूप विनाशकारी नतीजों जैसे मुद्दों पर बहस करने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम सम्बंधित और अन्य महत्वपूर्ण लम्बित विधेयकों को पारित करने की बजाए संसद को हंगामें की भेंट चढा दिया गया। सदन की बैठक के पहले दिन ही विपक्ष द्वारा किसी न किसी मुद्दे को लेकर घोषणा कर दी गई कि अगले दिन हम सदन नहीं चलने देंगे। किसी भी घोटाले को लेकर विपक्ष विशेषकर भाजपा द्वारा यूपीए सरकार पर टेलिविजन के ज़रिए आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा गया कि देश की जनता सरकार से जवाब चाहती है परंतु सरकार कोई जवाब नहीं देती।

गौरतलब है कि संसद की बैठक तो चलने नहीं दी जाती जो कि सरकार से जवाब मांगने व बहस करने का उपयुक्त व संवैधानिक स्थान है। शायद भाजपा को आशंका होगी कि बहस के दौरान कहीं उनके कार्यकाल में हुए घोटाले उजागर न हो जाए। अधिकांश मौकों पर 'सहमति' बनाने के नाम पर कांग्रेस सरकार ने केवल भाजपा से बातचीत की और अन्य विपक्षी पार्टियों की जानबूझ कर उपेक्षा की। दोनों मुख्य पार्टियां–कांग्रेस और भाजपा–नव उदारवादी नीतियों की समर्थक हैं और दोनों ही आर्थिक नीतियों पर किसी भी बहस से बचने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। इस प्रकार संसद को प्रभावहीन बनाने के सतत् प्रयास रहते हैं।

संसद के दोनों सदनों में अलग तेलंगाना राज्य के गठन के सम्बन्ध में बिल पेश करते समय बड़ी शर्मनाक घटनाएं घटित हुई। लोकसभा में तेलंगाना पर बहस के दौरान एक कांग्रेसी सांसद ने सदन में मिर्च का चूरा छिड़क दिया जिससे कई सांसद पीड़ित हुए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। कई सदस्यों ने अराजक स्थितियां पैदा की जिससे कुछ समय अन्य सदस्यों को अपने नेताओं की रक्षा करने के लिए उनकी घेराबंदी करनी पड़ी क्योंकि उन नेताओं पर शारिरिक हमले की आशंका थी। राज्यसभा में तेलुगू देशम के एक सदस्य ने सदन के महासचिव से कागजात छीन लिए। कुछ अन्य सदस्य विभिन्न प्रकार से अशोभनीय व असंसदीय व्यवहार कर रहे थे। कोयला घोटाला, टू–जी स्पैक्ट्रम घोटाला आदि मुद्दों पर संसद में बहस करने की अपेक्षा सदन की संसदीय कार्यवाही को पूरी तरह से ठप कर दिया और हंगामे की भेंट चढ़ा दिया।

राज्य विधानसभा व विधान परिषदों में विधायक भी सांसदों से पीछे नहीं रहे। जम्मू एवम् कश्मीर विधानसभा में एक पीडीपी सदस्य जब स्पीकर के सामने आकर नारे लगाकर कार्यवाही में लगातार रूकावट डाल रहा था तो स्पीकर ने मार्शल को उसे सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। जब मार्शल इस आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ा तो उक्त विधायक ने मार्शल को ही एक थप्पड़ जड़ दिया। उत्तर प्रदेश में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में जब राज्यपाल अपना पारम्परिक संबोधन कर रहे थे तब बसपा और आर एल डी विधायकों ने कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। बसपा सदस्य बैनर लेकर बैंचों पर खड़े होकर लगातार नारे लगाते रहे, तो आर एल डी विधायकों ने अपने कुर्ते उतार फेंके और नंगे बदन हो गए। आन्ध्रप्रदेश विधानसभा में तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे को लेकर विधानसभा के सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दिया और कोई विधायी कार्य नहीं करने दिया।

लोकसभा व विधानसभा में चुनाव जीतने व सत्ता प्राप्त करने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचारी, दागी, बाहुबली व अपराधिक पृष्ठभूमि के लोग़ों तथा दलबदलुओं को चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाने में कोई संकोच नहीं करते। जब ऐसे लोग चुनाव जीतकर लोकसभा/विधानसभा/ में पहुंचते हैं तो उनकी संसदीय कार्यों व संसदीय मर्यादा को बनाए रखने में कोई रूचि नहीं होती बल्कि वे तो संसद/विधानसभा की कार्यवाही के दौरान गतिरोध उत्पन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे संसद/विधानसभा की गरिमा को ही ठेस पहुंचती है। इसलिए राजनीति में बढते अपराधीकरण के विरुद्ध लड़ने की आवश्यकता है।

एक अन्य चिंताजनक प्रवृति है संसद और राज्य विधान सभा के सत्र की अवधि का लगातार कम होते जाना। सत्र को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन चलाने की मांग होती रही है। परंतु इसकी बजाए शासक पार्टियों तथा विपक्षी दलों के व्यवहार के कारण सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही है। यह रूझान यूपीए सरकार के दौरान भी हुआ और जब भाजपा के नेतृत्व वाला एन डीए सत्ता में था तब भी यही हुआ। यह प्रवृति संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है।

एनडीए शासन काल में संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अमेरिका की तर्ज पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित करने में असफल होने पर भाजपा ने 16 वीं लोक सभा के चुनाव के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली की नकल करते हुए मोदी को पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और चुनाव प्रचार इस ढंग से किया जा रहा है जैसे कि लोकसभा का चुनाव न होकर सीधा प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो रहा है। भाजपा की बजाए मोदी के लिए व मोदी सरकार के नाम से देश भर में वोट मांगे जा रहे हैं। यह एक तरह से संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर मोदी के जरिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली स्थापित करने का कुत्सित प्रयास है।

इन तमाम शर्मनाक व घृणित घटनाओं से संसद और विधायिकाओं की छवि को आघात पहुंचा है। सांसदों और विधायकों के व्यवहार से जहां हमारे राजनीतिक नेतृत्व में लगातार हो रहे गिरावट का पता चलता है वहीं यह संसदीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। इसके साथ–साथ संसदीय लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास भी कम होता जा रहा है। आशंका है कि जनता में बढती निराशा के फलस्वरूप कहीं जनता का रूझान लोकतंत्र की बजाए तानाशाही की ओर न हो जाए।